

Under the FERA, Melayalam Plantations had to Indianize its capital before 31st March, 1978. Now it is learnt that those associated with the company have floated yet another Indian company, Malayalam Plantations (India) Ltd. in Cochin with the object of taking over the assets of the UK company. The authorized capital of the new company is only Rs. 5 crores whereas as per the balance sheet, the Indian assets of the UK company alone are more than Rs. 7 crores and by actual market valuation at current prices, more than Rs. 20 crores. It is also understood that some time ago in a statement filed with the Reserve Bank, the Company had given the value of net assets at Rs. 25 crores or around. The shares of this UK company are quoted in the London share market at 31d. for a 10d. share. It was quoted earlier even at 57-1/2d. Among the directors of the New Indian company, 2 of them are employees, one legal adviser, one stock broker and others interested directors. Thus it is a clear attempt to frustrate the legislative intentions of the Parliament and circumvent the FERA rules of Indianization. If this proposed transaction, based on bogus figures, is allowed, the Government will lose huge amounts by way of stamp duty, registration fee and other taxes.

Here, I would invite the attention of Mr. Mohan Dharis. This company's bulk acreage has been in rubber, and it has been known as a rubber company, indicated even by the classification for long by the share columns of the *Financial Times*, London as a rubber company. In India they have always enjoyed all the facilities of a rubber company and still have 22,126 acres of rubber as against 18,064 acres of tea. Further, to reduce rubber acreage to pass off as a tea company large areas of rubber plantations are being cleared after immature slaughter tapping. This is nothing but wanton destruction of our plantation wealth.

As the House knows, a tea company can have 76 per cent foreign holdings while for other companies it can only be 40 per cent. So, they are clearly trying for an alternate method to circumvent the law of the land. As this is likely to frustrate the efforts of Parliament and Government to reduce the dependence on foreign capital, the Finance Minister and the Commerce Minister may make a statement on the issues I have just raised.

(iii) REPORTED TRAFFICKING IN GIRLS
IN RUDRAPUR IN DEORIA DIST. OF
UTTAR PRADESH

डा० रामजी सिंह (भागलपुर) :
अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत एक विशेष महत्व का प्रश्न आप की सेवा में उपस्थित करना चाहता हूँ। अभी हाल में आप ने अखबारों में देखा होगा कि बालिकाओं के क्रय-विक्रय का एक अन्तर्राष्ट्रीय अपराध गिरोह उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रघुरपुर स्थान पर पकड़ा गया है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 6 महीनों में 10 दर्जन ऐसी निर्दोष बालिकाओं का क्रय-विक्रय हुआ और सब से दुर्भाग्य की बात यह है कि ऐसी बालिकायें मुख्यतः ग्रहिन्दी भाषी क्षेत्र केरल, कर्णाटक, पश्चिमी बंगाल और आदिवासी क्षेत्रों से भगाई गई हैं। यह एक राष्ट्रीय चिन्ता का विषय है कि जहाँ विश्व भर में अन्तर्राष्ट्रीय नारी मुक्ति की चर्चा होती है, वहाँ भारत जैसे नारी को पूजने वाले देश में यह कुत्सित गणपार चल रहा है।

मैं सरकार से अपील करता हूँ कि सरकार इस प्रकार के दुष्कर्म को जड़-मूल से उन्मूलन कर देने के लिए एक विशेष अपराध-सेल की स्थापना करे।

(iv) REPORTED CLOSURE OF R.B.H.M.
JUTE MILLS, KATIHAR, BEHAR

श्री युधराज : (कटिहार) : अध्यक्ष महोदय, विगत दो वर्षों के बिहार राज्य स्थित आर० बी० एच० एम० जूट मिल्स,

[श्री युकारज]

कटिहार की बन्दी के फलस्वरूप लगभग चार हजार मजदूर और उन पर आश्रित बीसों हजार उन के पारिवारिक सदस्य भूखों तड़प-तड़प कर मर रहे हैं। जब श्रमिकों की स्थिति चिन्ताजनक दीख पड़ी तो जिला पदाधिकारी, कटिहार के प्रतिवेदन पर लगभग 6 लाख रुपये के मुफ्त खाद्यान्न का वितरण श्रमिकों के बच्चों एवं वहनों के बीच कराया गया। परन्तु दो माह तक जल कर सहाय्य वितरणबन्द कर दिया गया। उत्तरी बिहार का एकमात्र यह सब से बड़ा जूट उद्योग है जो प्रबन्धन की कुव्यवस्था के कारण बन्द है।

कटिहार उत्तर पूर्वीय भारत का प्रवेश द्वार है और उत्तरी बिहार की एक-मात्र नकदी-फसल जूट है जिसे किसान इस मिन में व्यापारियों के द्वारा बेचते थे। कटिहार, पूर्णिया सहरसा, भागलपुर-उत्तर आदि जिलों के बीच स्थित अकेला यह जूट कारखाना सब से बड़ा जूट का खरीदार था। लगभग चार हजार मजदूर तीन-तीन पालियों (शिफ्ट) में काम करते थे। ये मजदूर और इन पर आश्रित परिवार सभी भूखों मर रहे हैं। लगभग तीन सौ मजदूर भूखों, भ्रनाहार, कुपोषण तत्व पर प्राघातित रहने के कारण मर गये और उन की भ्रनाहार मौत जारी है। कोई दिन ऐसा नहीं बीतता है कि एक-आध मजदूर न मरते हों। जो शेष जीवित हैं उन की शारीरिक स्थिति नर-कंकाल जैसी हो गई है। बिहार राज्य का यह इलाका सब से गरीब और पिछड़ा हुआ है। प्रधान मंत्री, वाणिज्य मंत्री श्री मोहन धारिया, श्रम मंत्री, उद्योग मंत्री, आदि, सभी बरिष्ठ व्यक्तियों से निवेदन किये गये, परन्तु अब तक कारखाना चालू नहीं हो सका। थोड़े दिनों के बाद जूट वाणिज्य से उद्योग में हस्तांतरित कर दिया गया और अब जूट उद्योग-विभाग में आ गया है।

अतः जूट उत्पादकों एवं मिल के श्रमिकों तथा उन पर आश्रित परिवार बूढ़े, बच्चे, मां-बहनों के प्राण रक्षार्थ भारत० बी०एच०एम० जूट मिल्स, कटिहार को टेक-आवर कर काल-बद्ध कार्यक्रम की तरह शीघ्रातिशीघ्र चालू करने की ओर में सरकार का ध्यान द्राष्ट्य करता हूँ।

(v) REPORTED POWER POSITION IN MAHARASHTRA DUE TO ACUTE SHORTAGE OF COAL

SHRI VASANT SATHE (Akola): It is reported that the power position in Maharashtra State has become critical due to acute shortage of coal. The super thermal power station at Koradi has got stocks sufficient for a day only. The nearby Khaper Kheda power station has stocks for only 36 hours. One of the 25 M.W. set at Khaper Kheda has already been shut down because of lack of coal. If no coal reaches Koradi within the next 24 hours, one 120 M.W. set there would have to be shut down as reported by Member, Technical, Maharashtra State Electricity Board.

Since power from Koradi goes far into Western Maharashtra upto Sholapur, Karad etc, the resultant power shortage and load shedding would affect all parts of the State. It is further reported that barring Parli Vajinath which is fed by Singarenj coalfields, Ballapur and other power stations in Maharashtra have four to six days stock of coal while normally they should have at least 15 days to a month stock.

Repeated efforts by the Board to prevail upon the WCL to ensure full and regular supplies of coal to power stations in Maharashtra had not borne fruit. The matter was taken up at the highest level by the Board, even upto the Union Energy Minister but to no avail. It is reported that lack of coal would delay the commissioning of the new 200 megawatt set at Koradi power station from which we